



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, दिसम्बर 13, 2007/अग्रहायण 22, 1929

No. 372]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2007/AGRAHAYANA 22, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना (निर्णायक समीक्षा)

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2007

विषय: इंडोनेशिया तथा चीन जन गण के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फ्लोट ग्लास पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

सं. 15/1/2007-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क का आकलन और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इंडोनेशिया तथा चीन से फ्लोट ग्लास के आयात के संबंध में दिनांक 20.11.2002 की अधिसूचना सं० 14/19/2002-डीजीएडी के तहत अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और दिनांक 7.1.2003 की अधिसूचना सं० 7/2003-सीमाशुल्क के तहत केन्द्र सरकार द्वारा यह अनंतिम शुल्क लगाया गया। अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 22.8.2003 की अधिसूचना सं० 14/19/2002 में जारी किए गए थे और दिनांक 12.11.2003 की अधिसूचना सं० 165/2003-सीमाशुल्क के तहत निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया।

2. समीक्षा तथा जाँच शुरुआत हेतु आधार

मौजूदा आवेदन में सेंट गोंबेन ग्लास इंडिया लिमिटेड, श्रीपेरुंबदूर, तमिलनाडु (जिसे एतदपश्चात याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है कि वे देश में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन के 100 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं (अन्य दो

उत्पादकों अर्थात् असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड तथा गुजरात गार्जियन लि० ने कथित रूप से जाँच की प्रस्तावित अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। याचिकाकर्ता ने चेतावनी पत्र के उत्तर में इंडोनेशिया तथा चीन जन गण के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने हेतु समीक्षा जाँच करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अपने आवेदन में याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के साथ दावा किया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा दोबारा होने की संभावना है। उन्होंने अनुरोध किया है कि ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं के तहत संबद्ध वस्तु पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क को और 5 वर्ष के लिए जारी रखा जाए।

आवेदन की जाँच के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी शुल्क, जो पहलेसे लागू है, की समाप्ति की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति संबंधी याचिकाकर्ता के दावे की जाँच के लिए यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9 क के उपबंध के तहत इस स्थिति में प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करना उचित होगा।

3. विचाराधीन उत्पाद

इस निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद पारदर्शी तथा रंजित किस्म का (हरे कांच के अलावा) 2 मि०मी० से 12 मि०मी० मोटाई वाला (दोनों मोटाई शामिल हैं) फ्लोट ग्लास है जिसमें साज-सज्जा, औद्योगिक या ऑटोमोटिव उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रसंस्कृत कांच शामिल नहीं है।

चूँकि वर्तमान जाँच समीक्षा जाँच है; विचाराधीन उत्पाद मूल जाँच में परिभाषित उत्पाद के समान रहेगा क्योंकि उसके बाद की अवधि के दौरान उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण विकास अथवा परिवर्तन नहीं हुआ है।

4. शामिल देश

मौजूदा जाँचों में शामिल देश इंडोनेशिया तथा चीन जन गण हैं (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है)।

5. प्रक्रिया

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार दिनांक 22.8.2003 की अधिसूचना सं० 14/19/2002-डी जी ए डी के तहत जारी अंतिम परिणाम तथा दिनांक 12.11.2003 की अधिसूचना सं० 16/2003-सीमाशुल्क के तहत लागू अंतिम शुल्क

की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी इस बात की समीक्षा करने के लिए एतद्वारा जांच शुरू करते हैं कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से संबद्ध देशों के मूल के या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटन और उससे होने वाली क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इस समीक्षा में 22.8.2003 की अधिसूचना सं० 14/19/2002 डी जी ए डी के सभी पहलू शामिल हैं (मूल जाँच के अंतिम परिणाम)। प्राधिकारी का प्रस्ताव उपर्युक्त नियमों के अनुसार अनुच्छेद 2 में यथा उल्लिखित आवेदक, जिसका भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है, को घरेलू उद्योग के रूप में मानने का है।

6. जाँच अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि 1.07.2006 से 30.06.2007 (12 माह) है। तथापि, क्षति विश्लेषण में जाँच अवधि तथा जाँच अवधि से पूर्व के तीन वर्ष अर्थात् जनवरी-2004 - दिसम्बर, 2004, जनवरी, 2005 - दिसम्बर, 2005 तथा जनवरी, 2006 - दिसम्बर, 2006 शामिल होंगे।

7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय(डी जी ए डी)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

भारत सरकार

कमरा सं० 240, उद्योग भवन

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

ऊपर उल्लिखित नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी जाँचाधीन वस्तु के ऐसे औद्योगिक प्रयोक्ताओं तथा प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को अवसर दे रहे हैं जो पाटन, क्षति तथा हानि के संबंध में जाँच से संबंधित सूचना प्रस्तुत कर सकें। कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

8. समय सीमा

क. सामान्य समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से पूर्व पहुँच जानी चाहिए। परिचित निर्यातक तथा आयातक, जिन्हें अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से भेजे गए पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. बाजार अर्थव्यवस्था देश के चयन हेतु निर्धारित समय सीमा

इस जाँच से जुड़े हितबद्ध पक्ष ताईवान के औचित्य पर, जिसे इस शुरुआत अधिसूचना के पैरा 5 में चीन जन गण के संदर्भ में सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में परिकल्पित किया गया है, टिप्पणी कर सकते हैं। ये टिप्पणियाँ इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार (4) सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए।

9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION (SUNSET REVIEW)

New Delhi, the 13th December, 2007

Subject: Initiation of Sunset Review regarding anti-dumping duty imposed on Float Glass originating in or exported from Indonesia and China-PR.

No. 15/1/2007-DGAD.— The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional duty concerning imports of Float Glass from Indonesia and China vide Notification No. 14/19/2002-DGAD Dated 20.11.2002 and provisional Anti Dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 7/2003-Customs Dated 7.1.2003. Final Findings were issued vide Notification No. 14/19/2002-DGAD Dated 22.8.2003 and definitive duty was imposed vide Notification No 165/2003-Customs dated 12.11.2003.

2. Grounds for review and initiation.

The present application has been filed by M/s. Saint Gobain Glass India Limited, Sriperumbudur, Tamil Nadu (hereinafter referred to as applicant). It has been claimed by the applicant that they represent 100% of the total production of subject goods in the country (other two producers viz. Asahi India Glass Ltd. and Gujarat Guardian Ltd. are stated to have imported the product under consideration during proposed Period of Investigation). As a response to the alert letter, the applicant has filed an application for carrying out review investigations for continuation of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from Indonesia and China-PR. In their application, the petitioner has claimed with prima facie evidence that cessation of anti dumping duty imposed on subject goods from subject countries is likely to lead to recurrence of dumping and injury and have requested for continuation of the anti-dumping duty imposed on subject goods under the above mentioned notifications for a further period of 5 years.

On the basis of examination of the application, the Designated Authority considers that the sunset review of the Anti-dumping duty imposed would be appropriate at this stage under the provision of section 9A of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended to investigate the claim of the applicant about reoccurrence of dumping and consequential injury to the Domestic Industry in case of cessation of Antidumping Duty, already in place.

3. Product under Consideration.

The product under consideration in this sunset review is Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm, (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes.

Since, the present investigation is a review investigation; product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation, as there has been no significant development or change in the product during the period thereafter.

4. Countries Involved.

The countries involved in the present investigations are Indonesia and China PR (also referred to as subject countries hereinafter).

5. Procedure.

Having decided to review the final findings issued vide Notification No.14/19/2002-DGAD Dated 22.8.2003 and final duty imposed by Notification No 165/2003-Customs dated 12.11.2003, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of anti dumping duty is likely to lead to recurrence of dumping and injury on imports of subject goods originating in or exported from subject countries, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995. The review covers all aspects of Notification No.14/19/2002-DGAD Dated 22.8.2003 (Final findings of the original investigations). The Authority proposes to consider applicant as mentioned in paragraph 2 as domestic industry in accordance with the Rules supra as it constitutes the major proportion of the production of the subject goods in India.

6. Period on Investigation

The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is from 01.07.2006 to 30.06.2007 (12 months). The period of injury examination would however include POI and three years prior to the POI i.e. January 2004 –December 2004, January 2005- December 2005 and January2006-December 2006.

7. Submission for information

The exporters in the subject countries, their Government through their Embassies / High commissions in India and importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Government of India,

Room No. 240,
Udyog Bhavan,
New Delhi-110107

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

8. Time Limit.

a) General Time Limits

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty (40) days from the date of the letter addressed to them separately.

b) Specific time limit for selection of market economy country

Interested parties to the investigation may wish to comment on the appropriateness of Taiwan, which, as mentioned in the Para 5 of this initiation notification, envisaged as a market economy country for the purpose of establishing normal value in respect of the China PR. These comments must be submitted within four (4) weeks from the date of publication of this notification.

9. Inspection of Public File.

In terms of Rule 6 (7), Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Addl. Secy. and Designated Authority